ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i9SE.2015.3272

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

मध्य प्रदेश के नगरों मे पर्यावरणीय समस्यायें

सविता केशरवानी
जे आर एफ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

साराँष
भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसकी कुल जनसंख्या 7 करोड़ 25 लाख है तथा नगरीय जनसंख्या 20069806 है मध्य प्रदेश मे नगरीकरण अनुपात 27.63ः है। जो राष्ट्रीय अनुपात से कम है। परंतु कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत के कई राज्यों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। वर्तमान मे मध्य प्रदेश मे प्रशासनिक रूप से 51 जिलों मे कुल 242 तहसील तथा 313 विकासखण्डों मे विभक्त है। राज्य के 14 जिलों मे नगर निगम है तथा कुल नगरो की संख्या 476 है। मध्य प्रदेश मे 4 महानगरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है तथा 28 नगर ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच है। ज्ञातव्य हो की राज्य मे 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों की कुल नगरीय जनसंख्या का अनुपात 60ः से ज्यादा है। परंतु राज्य मे नियोजित और रणनीतिक विकास के आभाव मे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं सामने आई हैं जिसके परिणाम स्वरूप नगरों मे आर्थिक, सामाजिक, और सास्कृतिक विकास की गति धीमी पड़ी है।
वर्तमान मे राज्य के नगरों मे पर्यावरणीय समस्याओं मे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मलवा निस्तारण की समस्या, जल निकासी की समस्या, जल भराव, अम्ल वर्षा , कुहासा और उष्मा द्वीप के रूप मे उभर रही है। जिससे पर्यावरण अवनयन, विकिरण, बीमारियॉ, प्रजातियों का विलोपन जैसी समस्याएं उभर रही है।
प्रस्तुत शोध पत्र मे उपर्युक्त समस्याओं के कारण, प्रभाव और उसके निदान हेतु रणनीतिक सुझाव दिया गया है जिसके क्रियान्वयन से नगरों की ये समस्याएं कम की जा सकती हैं और विकास के समावेशी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है जो न केवल नगरीय पर्यावरण को सीमित करेगा वरन समग्र पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को बल प्रदान करेगा।

प्रस्तावना
अधिवासीय प्रतिरूप मे किसी भी क्षेत्र मे यदि नियोजित रूप से विकास होता है तो वह क्षेत्र बेहतर जीवन स्तर और संतुलित आर्थिक विकास वाला होता है। यही सिद्धान्त नगरीकरण के संदर्भ मे भी देखा जा सकता है। वर्तमान मे नगरीकरण और नगरीय विकास भारत मे सबसे तेजी से उभरता हुआ परिदृश्य है। एक ओर नगरों मे बेहतर सुविधाएं, रोजगार के अवसर तथा विभिन्न प्रकर की सुविधाबों के वजी से नगरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य रूप से भारत के नगरों की संख्या मे वृद्धि का अनुपात कम और नगरीय जनसंख्या वृद्धि का अनुपात ज्यादा है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ नगरों मे ग्रामीण क्षेत्र से होने वाला पलायन भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत मे कुल नगरीय और ग्रामीण वृद्धि दर के अनुपात मे दुगुने का अन्तर है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001–2011 के दौरान जहॉ नगरीय वृद्धि दर 34.68ः रहा वहीं ग्रामीण वृद्धि दर 17.64ः रही। भारत मे ग्रामीण नगरीय अनुपात क्रमशः 67. 84ः और 32.16ः रहा परंतु कुल जनसंख्या वृद्धि के रूप मे नगरों मे बढ़ने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा है।
यद्यपि नगरीकरण सकरात्मक आर्थिक विकास का द्योतक है परंतु यह सही दिशा मे नही हो तो नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं और उन समस्याओं के साथ कई अन्य प्रकार की

सामाजिक आर्थि जटिलताओं का विस्तार हूता जाता है क्यों कि नगरों मे बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्रों मे दबाव, परिवहन प्रणाली मे अव्यवस्था, आधारभूत सुविधाएं यथा पेयजल, जल निकासी, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, स्वस्थ्य, पर्यावरण जैसे मुद्दे चुनौतीपूर्ण होते जाते हैं।

प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जबकी जनसंख्या की दृष्टि से 5 वॉ बड़ा राज्य है इसी प्रकार सकल नगरीय जनसंख्या के क्रम मे यह भारत का 6 वॉ सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश मे कुल 51 जिलों मे 476 नगरीय केन्द्र हैं जिसमे सभी वर्ग के नगर विद्यमान हैं। वर्ग अनुसार नगरों का वितरण निम्न तालिका मे सूचीबद्ध किया गया है;

क्रमान्क	नगरों का वर्ग	नगरों की संख्या
	वर्ग 1	32
	वर्ग 2	31
	वर्ग 3	113
	वर्ग 4	178
	वर्ग 5	113
	वर्ग 6	9
	कुल	476

स्रोतः जनगणना 2011;मध्य प्रदेश, संस्करण 2.

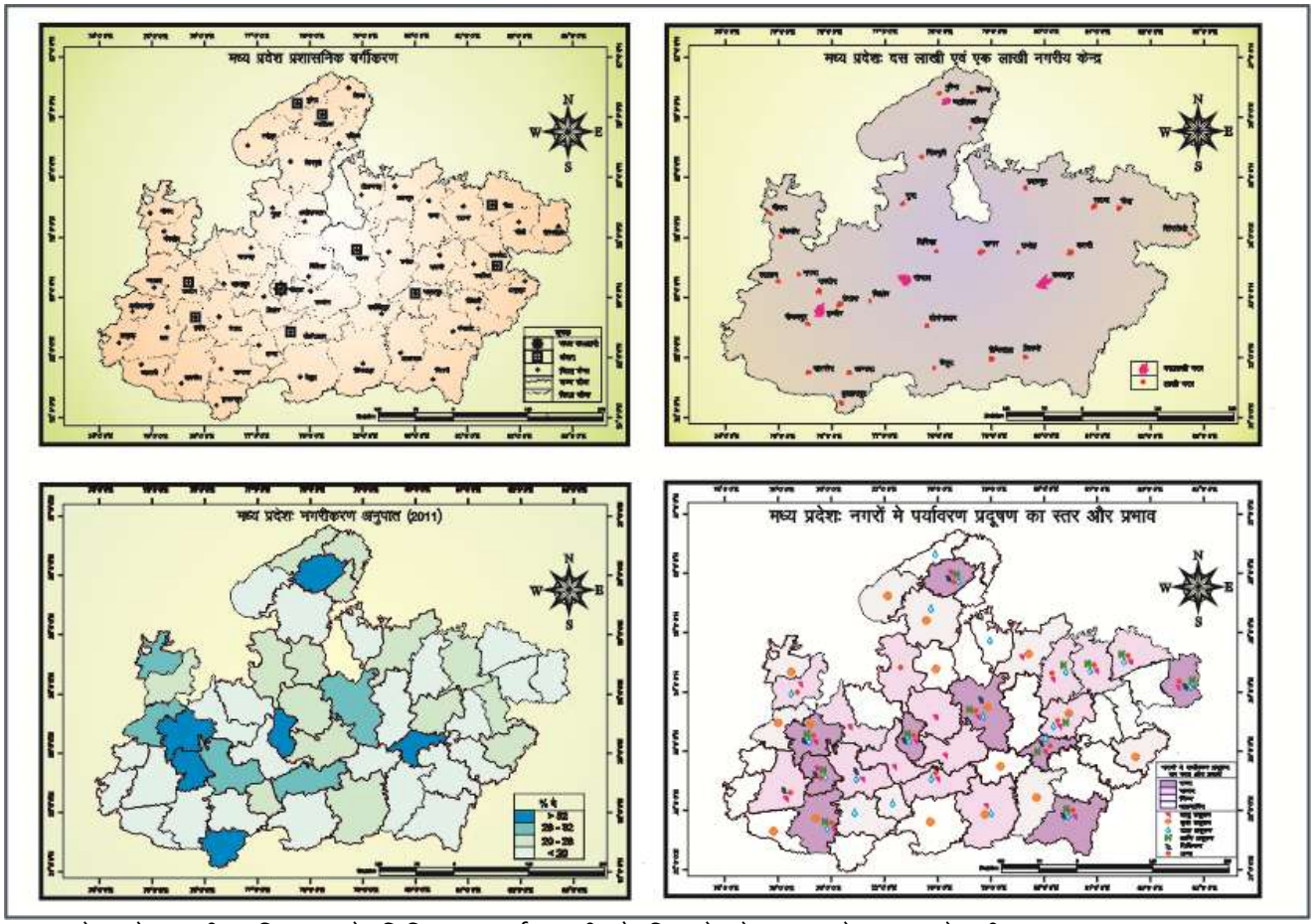

मध्य प्रदेश मे नगरीय वितरण मे विविधता पाई जाती है जिसमे से राज्य मे 4 नगरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है जो महानगर की श्रेणी मे आते है ये नगर क्रमशः इन्दौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर हैं। इसी प्रकार राज्य मे 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 28 है। मध्य प्रदेश मे वर्ग 1

ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)

प्रकार के नगरों मे कुल नगरीय जनसंख्या का 60ः हिस्सा विद्यमान है। यद्यपि मध्य प्रदेश मे नगरीय जनसंख्या अनुपात (27.63ः) राष्ट्रीय नगरीय अनुपात (32.16ः) से कम है परंतु यहॉ पर नगरीय पर्यावरणी समस्या मे व्यापकता और चुनौतीपूर्ण है। तथा बढते नगरीकरण के साथ ये पर्यावरणीय समस्याएं और जटिल होती जा रही है।

मध्य प्रदेश मे प्रमुख नगरीय समस्याएं बहुआयामी है एक ओर जहॉ मानवकृत नगरीय पर्यावरण और तथाकथित कन्क्रीट के जंगलों मे वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक पर्यावरण के स्तर और क्षेत्र मे गिरसवट हो रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय समस्याएं बढ़ते नगरीकरण के साथ साथ बढ़ रही है। क्यों कि जिस रफ्तार से नगरीकरण और नगरीय जनसंख्या मे वृद्धि हो रही है वही उस अनुपात मे नगरीय पर्यावरण का स्तर नही बढ़ रहा है बल्कि नगरीय पर्यावरण मे लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश मे नगरीय पर्यावरण की समस्याएं वर्ग 1 के नगरों मे ज्यादा जटिलता के साथ देखी जा सकती है। राज्य नगरीकरण प्रतिवेदन के अनुसार मध्य प्रदेश मे कुल नगरीय अपशिष्ट का 85ः नगरीय अपशिष्ट वर्ग 1 के नगरों द्वारा उत्सर्जित होता है। जब की ये नगर मात्र 60ः नगरीय जनसंख्या रखते हैं। इसी प्रकार 4 महानगरों मे जहॉ राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का 27ः नगरीय जनसंख्या रहती है वे 40ः तक नगरीय अपशिष्ट उत्सर्जन करते हैं। मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नगरीय समस्या है संसाधनों पर बढ़ता दबाव। नगरीय क्षेत्र मे प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन सीमित हैं लेकिन बढ़ते नगरीकरण के साथ संसाधनों की उपलब्धता अनुपात कम होता जा रहा है। जिसमे खुला स्थान मे कमी आ रही है। यद्यपि राज्य सरकार इसके लिए नए क्षेत्रों का चयन कर क्रमबद्ध नगरीकरण हेतु प्रयासरत है परंतु नगरों मे लगातार खुले स्थानों के क्षेत्र मे कमी आ रही है।

मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों मे प्रदूषण की प्रमुख समस्या सामने आ रही है उसमे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण और जल निकासी जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आ रही है। प्रदूषण की ये समस्याएं राज्य के 4 प्रमुख महानगरों मे चुनौतीपूर्ण है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी नगरों मे औद्योगिक इकाइयों की संख्या मे वृद्धि हो रही है परंतु इनका प्रतिरूप अनियोजित रूप से है जिससे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं सामने आ रही हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों मे सड़कों पर अधिक दबाव, उचित मानकों वाले वाहन की कमी, घरेलू कूड़ा–करकट, सीवेज, जैसे प्रमुख कारक है। इसके अलावा राज्य के कई मध्यम नगर भी प्रदूषण की श्रेणी मे राष्ट्रीय स्तर पर ऊचे स्थान पर हैं जिसमे उज्जैन, सिंगरौली, नीमच, रतलाम, देवास, सिवनी, सतना, पीथमपुर और कटनी प्रमुख है।

एक ओर मध्य प्रदेश मे कृत्रिम पर्यावरण मे वृद्धि हो रही है वहीं प्राकृतिक पारिस्थितिक क्षेत्र मे भी कमी आ रही है। इस आधार पर मध्य प्रदेश मे कई समस्याएं बढ़ रही है जिसमे पारिस्थितिक तंत्र मे असंतुलन, प्रजातियों का विलोपन, वन्य क्षेत्र मे कमी, कृत्रिम बीमारियो के दायरा और प्रभाव मे वृद्धि हो रही है। राज्य मे ऐसी कई औद्योगिक इकाइयां है जैसे चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, लुगदी उद्योग, रासायनिक खाद उद्योग, प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशा उद्योग जो समग्र रूप से प्रदूषण हेतु उत्तरदायी है इसी प्रकार कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं से उत्सर्जित धुंआ और राख नगरीय पर्यावरण के अवनयन और ह्रास का प्रमुख कारण है। राज्य के कई हिस्सों मे बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण के अवनयान के परिणाम स्वरूप जल भराव की समस्या, अम्ल वर्षा, कुहासा और उष्मा द्वीप जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है जिसके प्रवृत्ति और प्रभाव दोनों मे वृद्धि देखी जा रही है।

विकास और नगरीकरण लगभग एक दूसरे के पर्याय व मानक माने जाते है परंतु उपरोक्त नगरीय पर्यावरणीय समस्याओं के कारण नगररीकरण की इस प्रवृत्ति को संतुलित विकास नही कही जा सकता। नगरीकरण की गतिशीलता को सतत एवं संतुलित बनाए रखने के लिए बहुआयामी नियोजन की आवश्यकता है जिसमे सर्वप्रथम नगरीकरण के नियोजन और विकास के लिए बहुआयामी दिशा के साथ कार्या करना चाहिए। जिसमे नगर के सभी पक्षों का नियोजन की रूपरेखा शामिल होनी चाहिए साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का ऐसा विकास हो कि नगरों के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े तथा ग्रामीण नगरीय विभेदीकरण को कम किया जा सके। नगरीय पर्यावरणीय समस्याओं के नियोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि नगरीय क्षेत्र मे ज्यादा से ज्यादा हरित तकनीकी का प्रयोग और प्रोत्साहन दिया जाए। उच्च दक्षता वाली तकनीकी का विकास और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। नगरीय पर्यावरण प्रबंधन के लिए मूलभूत सुविधाओं को भी विकसित किया जाना चाहिए जिससे नगरीय जीवन शैली मे अवरोधकों की कमी आए। इन मूलभूत सुविधाओं

मे सड़क, नालियॉ, उर्जा आपूर्ति, परिवहन प्रणाली, यातायात साधन, जल निकासी, मलवा निस्तारण इत्यादि प्रमुख है।

नगरीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि नगरीय क्षेत्र मे उर्जा उपभोग प्रतिरूप मे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। उर्जा के विविध स्रोतों मे पारंपरिक उर्जा के स्थान पर गैर परंपरागत उर्जा स्रोत और नवीकरणीय उर्जा स्रोतों का विकास और उसका उपयोग किया जाना चाहिए इससे बढ़ती उर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तथा उर्जा दक्षता मे भी वृद्धि होगी तथा उर्जा विकल्पों की सुविधा भी बढ़ेगी।

वर्तमान समय मे विश्व के सभी नगरीय क्षेत्रों मे पर्यावरणीय समस्या एक चुनौती के रूप मे उभर की सामने आ रही है चाहे वह विकासशील देश हो या विकसित देश इस संदर्भ मे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय परिदृश्य मे नगरीय पर्यावरणीय समस्याओं को संज्ञान मे लेते हुए विकास कार्य को गतिशीलता प्रदान की जानी चाहिए जिससे सामाजिक असमानता व पर्यावरणीय विभेदीकरण मे वृद्धि न हो तथा संसाधनों का संतुलित प्रयोग करते हुए विकास किया जा सके।